(b) whether it is also a fact that STC, the only canalising agency for silver exports has charged these traders its usual commission of about Rs. 5 lakhs; and

(c) if so, what steps are being taken to ameliorate the conditions of these traders?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG): (a) Government have received representations from Silver Traders requesting for grant of permission for export of silver against contracts with S.T.C. prior to ban on exports.

(b) Yes, Sir.

(c) It has been decided to allow export in cases fulfilling certain specified criteria.

Premission to ply Tourist and Civil Planes to Jammu and Kashmir Government

6305. SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether the Jammu and Kashmir Government have approached the Central Government to give permission to them (Kashmir Government) to ply their own tourist and civil planes;

(b) if so, whether this is due to India Government's inability to ply more planes to Jammu and Kashmir State that require greater number of planes to carry tourists to Jammu and Kashmir area than the number which India Government ply to that State; and

(c) whether Jammu and Kashmir going tourists are stranded for days together due to non-availability of accommodation to and fro Jammu and Kashmir State area?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURU SHOTTAM KAUSHIK): (a) No, Sir.

(b) and (c). Indian Airlines has provided adequate capacity to facilitate movement of tourists to Jammu and Kashmir. It also operates additional flights as and when necessary.

लुधियाना में हवाई अड्डा

6306. चौधरी बलबीर सिंह :
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना में होजरी उद्योगों में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए पंजाब सरकार तथा वहां के लोगों ने केन्द्र सरकार से वहां हवाई अड्डा स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वहां हवाई अड्डे का निर्माण संभवतः कब तक कर दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा लुधियाना के लिए इस आधार पर विमान सेवाओं का परिचालन करने का प्रस्ताव किया था कि यदि आवश्यक हो तो वह सरकार इसके लिए उपदान देने को भी तैयार थी। यद्यपि लुधियाना पंजाब राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में से एक है, इंडियन एयरलाइन्स के लिए अपने टर्बो प्राप विमानों की सीमित संख्या को दृष्टि में रखते हुए, अपनी विमान सेवाओं को लुधियाना तक बढ़ाना संभव नहीं है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि लुधियाना भी

आबादी वाले उन 50 केन्द्रों में से एक है जिनकी तीसरी वायु सेवाओं के परिचालन संबंधी विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है । समिति की सिफारिशों की फिलहाल सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

पंजाब में जनता होटल

6307. चौधरी बलबीर सिंह :
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में जनता होटल खोलने के बारे में सरकार की कोई योजना है ताकि लोगों को 5/4 स्टार होटलों में न जाना पड़े जो कि बहुत महंगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये होटल 1979-80 में किन स्थानों में खोले जायेंगे और ये कब तक तैयार हो जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तथा (ख). पंचवर्षीय योजना 1978–83 में, संसाधनों पर निर्भर करते हुए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के चार महानगरों में 1250 बैड वाले यात्री निवासों (जनता होटलों) के निर्माण और अन्य केन्द्रों पर अपेक्षाकृत छोटे यूनिटों के निर्माण की जिनका निर्धारण एक सर्वेक्षण कराने के बाद किया जाएगा, परिकल्पना की गई है । केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत पंजाब में यात्री निवासों (जनता होटलों) के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । यदि गैर सरकारी उद्यमकर्ता जनता होटलों के निर्माण में रुचि रखते हों तो उन्हें ऐसा करने के लिए हर संभव प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

Amount outstandng under P.L.-480

6308. CHOWDHRY BALBIR SINGH:

SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV:

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) the amount outstanding against the country under P.L.-480 and the full details thereof; and

(b) whether Government have to pay interest thereon also?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) There is no rupee amount under P.L. 480 outstanding against the Government of India. The US Government made a grant of their P.L. 480 rupee holdings to the Government of India in February, 1974 and the said funds were extinguished by that grant.

During the year 1967 to 1978, the U.S. also supplied under P.L. 480 certain agricultural commodities against long-term loans repayable in dollars. The outstanding amount of such loans repayable in dollars stood at $ 656.34 million as on 1-10-78.

(b) The interest rate on the outstanding P.L. 480 dollar loans is between 2 to 3 per cent per annum.